नवभारत टाइम्स

फाल्गुन 8 शक 1923 ■ माघ पूर्णिमा विक्रम 2058 ■ नई दिल्ली ■ बुधवार 27 फरवरी 2002 ■ वर्ष 56 संख्या 58 ■ मूल्य 2 रु. ■ पृष्ठ 10+4=14 ■ महानगर

आर्थिक समीक्षा पर उद्योग जगत की प्रतिक्रिया

रियायतें खत्म करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली (वार्ता): आर्थिक समीक्षा में वस्तुओं के करारोपण और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर ढांचे को विश्व बाजार के अनुरूप युक्तिसंगत बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा संसद के दोनों सदनों में मंगलवार को रखी गई वर्ष 2001-2002 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि संघीय कर ढांचे में समय के साथ महत्वपूर्ण सुधार हुआ है लेकिन अभी भी करारोपण और आयात शुल्कों में काफी सुधार की आवश्यकता है। समीक्षा के मुताबिक विभिन्न करों में दी गई रियायतों और छूटों का निराकरण किया जाना चाहिए। समीक्षा में कहा गया है कि वर्ष दर वर्ष सीमा शुल्क दरों में कमी को देखते हुए इसके आधार को व्यापक बनाया जाना अनिवार्य है।

दसवीं योजना के लिए कर नीति तथा कर प्रशासन संबंधी परामर्शदात्री दल की सिफारिशों के अनुसार व्यक्तिगत आयकर की अधिकतम सीमा को 30 प्रतिशत पर बनाए रखने पर जोर दिया गया है। आर्थिक समीक्षा में आयकर अधिनियम 80. 88 और 80 तथा 10 की 15 धाराओं के तहत कर रियायतों को समाप्त किया जाना चाहिए। समीक्षा के अनुसार कंपनी कर की अधिकतम दर भी व्यक्तिगत आयकर की अधिकतम दर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अर्थात इसे भी 30 प्रतिशत पर रखा जाना चाहिए। विदेशी कंपनियों की करों की दर भी घरेलू कंपनियों के बराबरी पर लाने के उपाय किए जाने चाहिए। इसमें कहा गया है कि न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को पुनर्गठित कर समायोजित किया जाना चाहिए।

समीक्षा में कहा गया है कि सलाहकार दल की सिफारिशों के मुताबिक 35 प्रतिशत की उच्चतम सीमा शुल्क दर अभी भी दुनिया की उच्चतम दरों में है, इसे 2002-2003 के बजट में घटाकर 25 प्रतिशत, इससे अगले वर्ष 25 प्रतिशत और 2004-2005 में घटाकर 15 प्रतिशत पर लाया जाना चाहिए। समीक्षा के मुताबिक यथासंभव अधिक से अधिक छूटों को समाप्त किया जना चाहिए और 16 प्रतिशत का प्रतिकारी शुल्क बिना किसी छूट के समान रूप से लगाया जाना चाहिए।

सरकारी निवेश बढ़ाने पर जोर

नई दिल्ली (वार्ता): उद्योग व्यापार मंडलों ने 2001-02 की आर्थिक समीक्षा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि औद्योगिक उत्पादन में गिरावट को देखते हुए बजट में सरकारी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष संजीव गोयनका ने आर्थिक समीक्षा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष में कृषि और संबधित क्षेत्र की वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत होने का अनुमान आशा की किरण है। फिक्की के अध्यक्ष आर.एस. लोढ़ा ने आर्थिक समीक्षा में दसवीं योजना के दौरान आठ प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य हासिल करने के लिए आर्थिक सुधारों पर बल दिया है और उम्मीद जताई है कि वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में इस प्रकार के कदम उठाएंगे।

पीएचडी अध्यक्ष अरुण कपूर ने समीक्षा में चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर में 5.4 प्रतिशत होने के अनुमान के बावजूद अर्थव्यवस्था का निराशाजनक परिदृश्य उभरा है। पीएचडी अध्यक्ष ने सार्वजनिक सेवाओं की पूरी कीमत वसूलने पर जोर दिया है।

एसोचैम अध्यक्ष के.के. नोहरिया ने कहा है कि समीक्षा से लगता है कि सरकार की वित्तीय स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास धन की कमी को देखते हुए आधारभूत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की नई वित्तीय तकनीकें ईजाद करने की आवश्यकता है।

भारतीय वित्त संस्थान के अध्यक्ष व निदेशक प्रो.जे.डी.अग्रवाल ने पिछले वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन और राजकोषीय प्रबंधन पर संतोष जताया है।

उनके मुताबिक अंतरराष्ट्रीय मंदी और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद भारत का जीडीपी काफी अच्छा रहा। कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में 5.7 प्रतिशत, उद्योग में 3.3 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर को भी उन्होंने संतोषजनक बताया है। राजकोषीय घाटे को 5.1 प्रतिशत तक स्थिर रखने के लिए उन्होंने सरकार की प्रशंसा की।

वाणिज्यिक संगठनों ने रेल बजट को संतुलित बताया

नई दिल्ली (एजेंसियां/वाप्र): उद्योग व व्यापार जगत ने रेल बजट की प्रशंसा करते हुए इसे संतुलित और बेहतर बताया है पर उद्योग संगठनों का यह भी कहना है कि देश में रेल परिवहन की क्षमता बढ़ाने के लिए और बड़े कदम उठाने की जरूरत है।

भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ (फिक्की) के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह लोढ़ा ने कहा है कि रेल मंत्री नीतीश कुमार ने माल भाड़े और यात्री किराए पर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया है। सीआईआई के अध्यक्ष संजीव गोयनका ने कहा है कि रेलवे सुरक्षा के लिए 1700 करोड़ रु. का कोष स्वागत योग्य है और इससे पुरानी रिण परिसम्पत्तियों के नवीनीकरण में मदद मिलेगी।

एसोचैम अध्यक्ष के.के. नोहरिया ने कहा कि 2002-03 का रेल बजट पिछले बजटों की तुलना में ज्यादा संतुलित और अच्छा है और इसमें रेल के खर्चों में कमी के प्रयास सराहनीय हैं।

पीएचडी अध्यक्ष अरुण कपूर ने कहा कि रेल बजट में अल्पकालिक उपायों को ही प्राथमिकता दी गई है । सेल के चेयरमैन अरविन्द पांडे ने रेल बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह संतुलित बजट है और विशेष रेल सुरक्षा फंड के जरिए ट्रैक का नवीनीकरण काफी आसान हो जाएगा। लोहा और इस्पात के माल भाड़े में कमी करने का भी उन्होंने स्वागत किया।

लेकिन यह भी कहा कि इस्पात के कच्चे माल पर भाड़ा बढ़ा देने से इस्पात का उत्पादन महंगा हो जाएगा और सेल पर 25 करोड़ रु. का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

भारतीय वित्त संस्थान के प्रो.जे.डी.अग्रवाल ने रेल बजट में परिचालन व्यय पर 1090 करोड़ रु. की बचत की सराहना की है।